

पत्र सं०-5/बजट (भ०नि०) 5-05/12 -सा०-...../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

विमलेश कुमार झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

पटना-15, दिनांक- 2014

विषय :- झंझारपुर अनुमंडल के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार-सह-अध्यक्ष, राज्य स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 991 दिनांक 22.12.2014 (प्रति संलग्न) द्वारा झंझारपुर अनुमंडल के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु पत्र भेजा गया है।

अतः अनुरोध है कि भूमि की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए झंझारपुर अनुमंडल के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

अनु०-उपरोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-5/बजट (भ०नि०) 5-05/12-सा०-.....¹⁴⁹ / पटना-15 दिनांक.....⁵⁻¹⁻¹⁵

प्रतिलिपि:-सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार-सह-अध्यक्ष, राज्य स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति पुराना नचिवालय पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याच प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

नीतीश मिश्रा
Nitish Mishra



मंत्री
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार
- सह -
अध्यक्ष
राज्यस्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति
बिहार
दिनांक / Dated : 22/12/14

पत्रांक / Ref No 991/सि

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना ।

विदित हो कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर एक पुराना अनुमंडल है, जिसकी स्थापना सन् 1972 ई0 में हुई थी जो यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मुख्यालय भी है। इस अनुमंडल के अधीन चार बड़े-बड़े प्रखंड— झंझारपुर, लखनौर, अंधराठाढी एवं मधेपुर अवस्थित हैं । यह अनुमंडल मिथिलांचल की हृदय स्थली है । आस-पास के लगभग 10 प्रखंडो की जनता के लिए यह एक प्रमुख वाणिज्यिक, व्यवसायिक एवं शैक्षणिक केन्द्र है । प्रशासनिक दृष्टि से भी इस अनुमंडल का अपना विशेष महत्व है ।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में सामान्य प्रशासन विभाग का योजना मद से 03 करोड़ 15 लाख 67 हजार 771 रूपये की लागत से अनुमंडल कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी। निर्माण कार्य अंतिम चरण में है । इस संबंध में विचारणीय है कि सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी के साथ-साथ अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों के आवासन की व्यवस्था हेतु कोई भवन उपलब्ध नहीं है । पदस्थापित पदाधिकारी या तो किराये के आवास में रहते हैं अथवा अन्य भवनों में येन-केन प्रकारेण आवासित हैं । यद्यपि इस अनुमंडल कार्यालय को आवासीय परिसर के निर्माण हेतु पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है । कर्णांकित सरकारी आवास के अभाव में पदाधिकारियों का आवासन असुरक्षित एवं अव्यवस्थित है । इसका कुप्रभाव प्रशासनिक कार्यों पर पड़ना भी अस्वाभाविक नहीं है ।

वर्णित परिपेक्ष्य में निर्माणाधीन झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय भवन के समीप उपलब्ध सरकारी भूमि पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों के आवासन हेतु आवासीय भवन एवं परिसर निर्माण कराने की दिशा में समुचित कार्रवाई करना चाहेंगे ।

शुभकामनाओं के साथ ।

Nitish Mishra
(नीतीश मिश्रा) 22.12.14